





# ओमिक्रोनः फिर लगेगा आंशिक लॉकडाउन ?

केंद्र ने राज्यों से कहा, जरूरत पड़े तो लागू हो प्रतिबंध

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र सांसित प्रदेशों को आगाह किया है। केंद्र ने जरूरत पड़ने पर राज्यों से कड़े प्रतिबंध लागू करने के लिए कहा है। जिसमें नई कम्पूटर सेषेंटिंग पर रोक लगाना और केंटेनमेंट जौन बनाना तथा शामिल है।

केंद्र ने राज्यों से ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए और साथ ही कोरोना मामलों पर लगातार ध्यान देने के लिए कहा है। यह निर्देश दिया गया है कि ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते केसें और कोरोना के बढ़ते मामलों के शुरुआती स्केट मिलने पर ही जरूरी उपाए भी किए जाएं।

ओमिक्रोन मामलों की संख्या 200 से अधिक होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि जिला स्तर पर कोरोना से प्रभावित के अनुसार करीब 54 मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में अभी तक के अंकड़ों के अनुसार करीब 54 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 54, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में



राज्यों को यह निर्देश दिया है। अधिकारिक अंकड़ों के अनुसार सात राज्यों में ओमिक्रोन का अंकड़ा दर्हाई का पार कर चुका है। इसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र में अभी तक के अंकड़ों के अनुसार करीब 54 मामले दर्ज किए गए हैं। जिसमें अन्यान्य केंद्रीय राज्यों की स्थापना, राज्यों खाड़ी सुरक्षा में पोषक अनाज को शामिल करना और कड़े राज्यों में कर्दान मिशन की स्थापना करना शामिल है। इसके बावजूद उत्पादन, वितरण और उपभोक्ताओं द्वारा मोटे अनाजों को अपनाने से जुड़ी कई चुनौतियां कायम हैं। वितरण प्रणाली के अंतर्गत, समय आ गया है कि हम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रमों का ध्यान 'कैलरी सिड्हू' से हटाकर ज्यादा विविध खाद्यान्न संकुल प्रदान करने पर लगाये, जिसमें मोटे अनाज को शामिल किया जाये, ताकि स्कूल जाने की आय से छोटे बच्चों और प्रजनन-योग्य महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाया जा सके। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 20 दिसंबर, 2021 को एक आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इस साझेदारी के तहत मोटे अनाज को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान दिया जायेगा और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कर्दान वर्ष होने के नाते इस अवसर पर भारत को ज्ञान के आदान-प्रदान के क्षेत्र में विवर का नेतृत्व करने में समर्थन दिया जायेगा। इसके अलावा, इस साझेदारी का लक्ष्य है छोटी जाते के किसानों के लिये तात्पात्रता आजीविका के अवसर बनाना, जलवाय परिवर्तन के देखते हुये क्षमताओं को अपनाना और खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना।

## नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये

नई दिल्ली। कर्दान फसलों (ज्वार, बाजरा, रागी, मुदवा, सावं, कोरोने, कुटकी, कंगनी, चीनी आदि मोटे अनाज) के महत्व को पहचान कर भारत सरकार ने 2018 को कर्दान वर्ष के रूप में मनाया था, ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र आपसमें 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कर्दान दिवस के रूप में धोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था। मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कर्दान उत्पादन दिवस के रूप में धोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया था। जिसमें अन्यान्य केंद्रीय राज्यों में लिखे पत्र में कहा गया है कि जिलों में जिला स्तर पर कोरोना से प्रभावित के अनुसार करीब 54 मामले दर्ज किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि जिला स्तर पर कोरोना से प्रभावित आवादी, इसके बढ़ते प्रसार, अस्पताल में मौजूद सुविधाएं, मैन पॉवर, कर्नेटमेंट जौन को बनाने और

## भारत में कई चीजों के वायदा व्यापार पर बैन

दिल्ली। भारत ने कई जिस्मों के वायदा व्यापार पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 2003 में वायदा व्यापार को अनुमति दिए जाने के बाद से इस क्षेत्र में यह सबसे बड़ा फैसला हो गया है। यह जिसका असर विभिन्न बाजारों पर देखा जाता है, असर भारतीय खाद्य तत्वों के व्यापारों के संगठन सोलेट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनुल चुरुवेंदी (डीएसटी) विभाग, भारत सरकार के विभिन्न व्यापार और इससे जुड़े क्षेत्रों में अभिन्न राह तय कर रहे हैं, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार का यह फैसला लाखों निवेशकों के लिए बुरी खबर बनकर आया जिसने इन जिस्मों में भारी निवेश किया हुआ है। यह फैसला तब दिया गया है कि जबकि कीमतों में आसान पर हो जाए। देखें, नजर आया। भारत ने पांच उत्पादकों वस्तुओं का वायदा व्यापार पर रोक लगा दी है। खाद्य तत्वों, गेंहुं और चावल जैसी मूलभूत चीजों की शामिल राहत है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार का यह फैसला लाखों निवेशकों के लिए बुरी खबर बनकर आया जिसने इन जिस्मों में भारी निवेश किया हुआ है। यह जीवन और नार्वें ने भी नए क्षेत्रों को थानों के लिए उत्पादन करने के लिए लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगायी है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार्टीवांटों लगाया गया है, यह तो संदेशवाहक को गातों मारने जैसा है।

तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। सरकार ने लोगों से जल्दी से जल्दी टीके लागाने की अपील की है। फैसले की ओर जिसका लॉकडाउन जैसी पार

संपादकीय

## **कृटनीतिक कामयाबी**

यह भारतीय कूटनीतिक कामयाबी ही कही जायेगी कि जिस समय इस्लामाबाद में इस्लामिक देशों के संगठन और आईसी के सदस्य देशों की अफगानिस्तान के मध्य पर बैठक हो रही थी उसी दिन भारत में आयोजित सम्मेलन में मध्य एशिया के पांच इस्लामिक देश भाग ले रहे थे। दरअसल, दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित तीसरे भारत-मध्य एशिया डायलॉग में उज्जेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान व कजाखस्तान के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की। वे इस्लामाबाद जाने के बजाय दिल्ली सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में जहां मध्य एशिया के इन देशों के बीच व्यापार संबंधी व क्षेत्रीय जुड़ाव पर बात हुई, वहीं अफगानिस्तान के मध्य पर गंभीर विमर्श हुआ। उल्लेखनीय है कि इन पांच देशों में से तीन ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्जेकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान के हालात पर इनकी चिंता भारत से मेल खाती है। इस सम्मेलन के बाद जारी सुयुक बयान में भारत ने इन पांचों देशों के साथ एक सुर में कहा कि बदले हालात में अब अफगानिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मनवीय सकट से ज़िद्दा रहे अफगानिस्तान की भरापूर मदद की जाये। निस्सदृष्ट भारत समेत इन देशों की क्षेत्रीय सुरक्षा को अफगानिस्तान में तालिबान के आने से खेतरा उत्पन्न हुआ है। इन पड़ासी देशों के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा है। दरअसल, अफगानिस्तान से अमेरिका व नाटो संगठन की वापसी के बाद तालिबान कब्जा होने से भारत की गंभीर भूमिका नहीं रह गई थी। एक बजह यह कि तालिबान पाक के गहरे प्रभाव में है और पाक नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में भारत की कोई भूमिका हो। लेकिन भारत ने कूटनीतिक प्रयासों से इस दिशा में अपनी भूमिका के लिये जगह बनाने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि दस नवंबर को भी इन मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अंजीत डोभाल की अध्यक्षता में दिल्ली सम्मेलन हुआ था। प्रत्यार्पण गत किं दिनों कुछ और एक दिन के ताजीगी गतिशीलता वालों का भी

महत्वपूर्ण यह कि इसमें रुस आर ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने मौजूद थे। दरअसल, भारत की सोच रही है कि वह मध्य एशिया के देशों से संबंध बेहतर करके अफगानिस्तान में अपने कृतीतिक हितों का पोषण कर पायेगा। इसमें भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ईरान रिश्त चाबहार बंदरगाह के जरिये मध्य एशिया के इन देशों से जुड़वा का लक्ष्य भी शामिल है, जिसमें इन देशों में आपसी व्यापार के लिये मालवाहक गलियारा बनाने पर सहमत होना भी शामिल है। अच्छी बात है कि भारत की विताओं में शामिल इन देशों ने अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर कारगर कार्रवाई पर सहमति जतायी। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रावधानों के अनुरूप अफगान धरती को आतंकवाद की उर्वरा भूमि बनाने से रोकने के सभी आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया। वहीं भारत समेत इन देशों के विदेश मंत्रियों ने सहमति जतायी कि जहां अफगानिस्तान की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा होनी चाहिए, वहीं सभी अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी वाली समावेशी सरकार बनाने का मार्ग प्रस्तुत हो, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। प्रयास हो कि अफगानिस्तान में मानवीय अधिकारों का सम्मान किया जाए। तालिबान सरकार बनने के बाद अफगानिस्तान की धरती से नशे के कारोबार फलने-फूलने पर चिंता जताते हुए इस पर रोक के लिये सख्त प्रयास करने की जरूरत बतायी गई। सभी सहमत थे कि नये अफगानिस्तान में यूएन की प्रभावी भूमिका हो। वक्त आ गया है कि मानवीय संकट को दूर करने के लिये तुरंत मदद पहुंचाई जाए। साथ ही जातीय अल्पसंख्यकों, महिलाओं व बच्चों के हितों को सरक्षण मिले। निस्संदेह, पाकिस्तान को इस बात की परेशानी होगी कि इस्लामाबाद में चालीस साल बाद हुए इस्लामिक देशों के सम्मेलन के समातर भारत ने मध्य एशियाई देशों के सम्मेलन के जरिये कुछ बढ़त तो हासिल कर ली है। निस्संदेह, जनवरी में होने वाले मध्य एशिया-भारत सम्मेलन के बाद यह मुहिम और विस्तार लेगी वही इस्लामाबाद में हुई ओआईसी की बैठक में पारित 31 मुद्दों वाले सकलपत्र में भी अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने व मानवीय सहायता पहुंचाने पर बल दिया गया।

खौफ में बाजार

मुंबई शेयर बाजार के सुचाकांक सेंसेक्स ने खोफ का इजहार कर दिया है 20 दिसम्बर को इसमें बुरी तरह गिरावट दर्ज की गई। एक महीने का हिसाब लगाएं, तो इसमें करीब सात फीसद की गिरावट देखी गई है। एक महीने में सात फीसद की गिरावट सेंसेक्स में तब दिख रही है, जब अर्थव्यवस्था में सुधार की बातें हो रही हैं। जब ऐसी बातें की राही हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। पटरी से उत्तरने का मामला दरअसल खौफ का मामला है और ओमीक्रोन ने पूरी दुनिया में खोफ पैदा कर दिया है। अर्थव्यवस्था और खास तौर पर शेयर बाजार को उमीदों और आशकाओं के अतिरिक्त में ही चलते हैं खोफ के अतिरिक्त में शेयर बाजार ढूँढ गया, इससे कई स्टर्टों पर चिंताएं पैदा हुई हैं। हाल में शेयर बाजार जब उछल रहा था तो कई कंपनियों ने अपने शेयर जारी किये थे और बहुत आसानी से अपने कारोबार के लिए पूंजी बाजार से जुटा ली थी। पर अब जब बाजार ढूँढ रहा है तब ऐसे बाजार से पूंजी जुटा पाना आसान ना होगा। यानी पूंजी की उपलब्धता पर अवरोध लगेगा। युतातक की तौर पर देखें, तो अभी तक करीब 150 मामले ही ओमीक्रोन के आए हैं, पर इन 150 मामलों के साथ वो द्वितीयां दोबारा स्रित उठाने लगी हैं जो अप्रैल मई 2021 के हाइदोसे के साथ जुड़ी हैं। जब अस्पताल के बाद अस्पताल लोग भटक रहे थे बैड उपलब्ध नहीं थे, आकसीजन उपलब्ध नहीं थी। कवा वैसा दोबारा होगा, इस सवाल का जवाब पछे तौर पर कोई नहीं दे सकता है। अभी तक कूल मिलाकर यह साफ हुआ है कि ओमीक्रोन बहुत ही संक्रामक है, बहुत तेज गति से लोगों को शिकार बना लेता है, पर यह मारक नहीं है। यानी जननानि की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ऐसा दुनिया भर का हाल का तजुरबा बताता है। पर कूल मिलाकर असावधानी नहीं बरता जानी चाहिए। और सरकारों की भी अपने आपातकालीन इंतजाम समय रहते दुरस्त कर लेने चाहिए। पर निवेश और खर्च का जो माहौल दोबारा आशकाओं से ग्रस्त हो गया है उसे पटरी पर आने में समय लगेगा। संकंट के वर्त या संकंट की आशकां में लोग खर्च को टालते हैं और बचाकर रखते हैं रकम इस डर से कि पता नहीं कब आपातकाल की जरूरत पड़ जाए।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

## जी नमस्कार, भाग यहां से

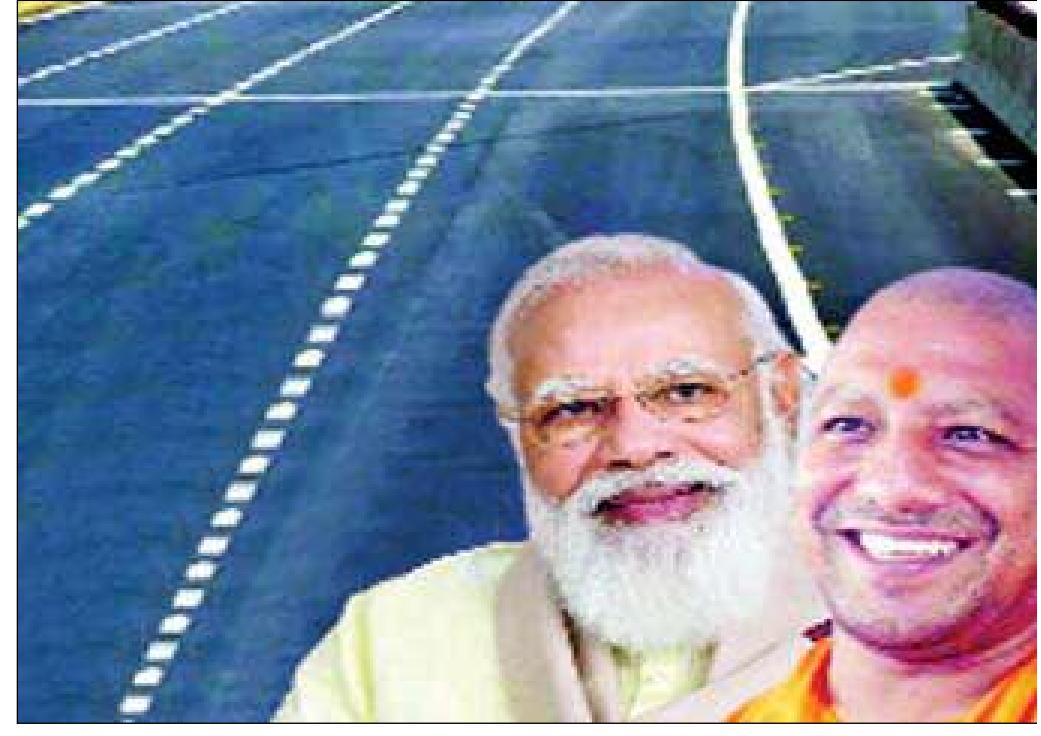
सर्दी का मौसम तो इस मुल्क में महीने दो महीनों को ही आता है, चुनाव का सीजन अलवता हमेशा रहता है और पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, नगर पालिका चुनाव, विधायक चुनाव, ऐमपी चुनाव जब नहीं चल रहे होते हैं, तो छात्र संघ के चुनाव और वो भी ना चल रहे होंगे तो रोटरी कलब लायर्स कलब के चुनाव यह मुल्क चुनाव से फ्री ना होता, टैंट माइक्र वालों का धंधा हमेशा चकाचक रहता है। इधर हाल में बहुत मामला उलटा पुलटा हो लिया है। अमेरिका से राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर आये थे, उन्हें भारत का पालिटिक्स कुछ यूं समझायी- आलोक पुराणिक यानी आपु-देखिये प्रोफेसर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह भूतपूर्व कांग्रेस वाले अब भाजपा के साथ हैं। जान ले लूंगा से अब मामला ये दोस्ती हम नहीं छोड़े तक आ गया है। अमेरिका प्रोफेसर उर्फ अप्रो-भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ज आइडियोलोजिकल भेद, वैचारिक भेद थे, वो खत्म हो गये क्या। आपु-हाहाहाहाहाहा-देखिये जब मैं हाहाहाहा कहूँ तो आप समझ लिया कीजिये विं आप ने कुछ चुटकुला टाइप बात कही है। औके आगे देखिये, सिद्ध कभी भाजपा के साथ थे, अब वह लगता तो है कांग्रेस के साथ हैं, पर लगता नहीं है कि वह कांग्रेस के साथ हैं। मतलब वह है बस इतना भर माना जा सकता है। अमेरिकन प्रोफेसर-ओके ममता बनर्जी किसके साथ हैं। आपु-ममता बनर्जी गोआ में उनवें साथ हैं, जो पहले कांग्रेस के साथ थे। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अब उनवें साथ हैं, जो पहले कांग्रेस के साथ थे। ममता बनर्जी बंगाल में किसी को साथ नहीं रखती, क्योंकि वही सब कुछ हैं। ममता बनर्जी महाराष्ट्र में शरद पवार वे साथ हैं और शरद पवार किसके साथ है, यह पता लगाना असंभव है। वेरो शरद पवार महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हैं, शिवसेना कुछ साल पहले भाजपा के साथ थी। राजस्थान में सचिन पायलेट यूं तो अशोक गहलोत के साथ हैं, पर अशोक गहलोत भी उनके साथ हैं, यह पता ना चलता। अप्रो-बहुत कनप्यूजन है ना। आपु-अगर आप पूरे कनप्यूजन हो गये हैं, तो समझ लीजिये कि आपने झाड़यन पालिटिक्स को समझ लिया। कुल मिलाकर हर नेता का हर नेता के साथ रिश्ता यही है-जी नमरकार, चल फूट यहाँ से।

# उत्तर प्रदेश : एक्सप्रेस-वे की राजनीति

**अवधेश कुमार**  
उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल पर गहराई से नजर डालें तो भाजपा ने डाल के दिनों में एक्सप्रेसवे को एक मुद्दे के रूप में सामने लाया है।  
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसम्बर को शाहजहांपुर में गंगा

एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। चुनावी विश्लेषक यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या भाजपा एक्सप्रेसवे के आधार पर इस बारे चुनावी रण में विजित होने की उम्मीद कर रही है? यह प्रश्न अख्याभाविक नहीं है। हालांकि एक्सप्रेसवे से चुनावी किले की विजय की पृष्ठभूमि नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में यहाँ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। हाँ, 2012 के चुनावों से पहले, वह उसका उद्घाटन नहीं कर पाई। बावजूद लोगों को पता था कि यह एक्सप्रेसवे मायावती ने बनवाया है। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया। अखिलेश ने 2017 के चुनावों में इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित भी किया 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की कैसी दुर्जी हुई यह बताने की आवश्यकता नहीं।

यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि भाजपा गंगा एकसप्रेसवे परियोजना को पश्चिमी उप्र में अपने चुनावी तरकस में एक बड़े तीर के रूप में रख रही है। उसे लगता है कि इस परियोजना का आकषण्ण क्षेत्र में ऐसा होगा जिससे कि सपा रालोद गढ़बंधन के साथ टिकैत के भारतीय किसान यूनियन के असर को भी कमजोर करेगा। किंतु यह भाजपा के मुद्दों में से एक है जिसके साथ वह कई चीजों को जोड़ती है। यह उसकी रणनीति है।



हांगा तभा उद्घान पूर्वाधल एक्सप्रेसव के उद्घान से पहल दावा कर दिया कि यह उनकी परियोजना थी और भाजपा केवल प्रधानमंत्री से इसका फीता कटवा रही है। अखिलेश ने गाजीपुर से लखनऊ के लिए पूर्वाधल एक्सप्रेसवे विजय रथ यात्रा शुरू कर दी। इतनी बात सही है कि पूर्वाधल एक्सप्रेसवे की योजना सपा सरकार में बनी किंतु इसके सारे कार्य और समय सीमा में योजना को पूरा करना तथा इसकी गुणवत्ता पहले की योजनाओं से बेहतर और क्षेत्रफल विस्तारित करने का काम योगी सरकार ने ही किया। आपने योजना बना दी इससे आप दावा के हकदार नहीं होते। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घान के पहले भी अखिलेश ने बयान दे दिया कि यह परियोजना तो मायावती ने शुरू की थी। जाहिर है, इसके असर का भय नहीं होता तो अखिलेश को इस तरह के बयान देने की आवश्यकता नहीं होती। उनके बयान से यह सवाल तो जनता उठाएगी ही अगर मायावती के समय की योजना थी तो आपके कार्यकाल में भी यह पूरी दियों नहीं हुई? यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि भाजपा गगा एक्सप्रेसवे परियोजना को पश्चिमी उप्र में अपने चुनावी तरकस में एक बड़े तीर के रूप में रख रही है। उसे लगता है कि इस परियोजना का आकर्षण क्षेत्र में ऐसा होगा जिससे कि सपा रालोद गढ़बंधन के साथ टिकैत के भारतीय किसान यूनियन के असर को भी कमजोर करेगा। किंतु यह भाजपा के मुहों में से एक है जिसके साथ वह कई चीजों को जोड़ती है। यह उसकी रणनीति है। प्रधानमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे को उप विकास को गति और शक्ति देने वाला बताते हुए जनता से कहा कि इससे एयरपोर्ट, मेट्रो, वाटरवेज, डिफेंस कॉरिडोर भी जोड़ा जाए और इसे फायरबर ऑप्टिक केबल, बिजली तार बिछाने में आमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में पश्चिमी उप्र के काटेनर वाराणसी के ड्राइपोर्ट के माध्यम से सीधे हल्दिया भेजा जाएंगे। यह एक्सप्रेसवे समाज के हर तबके को फायदा देगा। पहले की योजनाओं का न इतना विस्तारित खरलूप था और अखिलेश और मायावती जनता के अंदर एक्सप्रेसवे भाष्मी की ऐसी व्यापकता समझा पाते थे। प्रधानमंत्री ने उन बातें की वो सच भी हैं क्योंकि एक्सप्रेस वे केवल आवागमन का एक सामान्य साधन नहीं है। इससे आधुनिक विकास सहित सुरक्षा और कई व्यापक आयाम जुड़े हैं। यह सही है कि पश्चिमी उप्र की सामग्रिया इस माध्यम से वाराणसी पहुंच जाएगी। मार्ग के जरिए हल्दिया बंदरगाह आसानी से पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री ऐसे अवसरों का दूसरे रूप में भी उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए गंगा एक्सप्रेसवे शिलाचास कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले शाम होते ही सड़कों पर कलहराए जाते थे। पहले व्यापारी, कारोबारी घर से सुनिकलता था तो परिवार को चिंता होती थी, गरीब परिवर्त दूसरे राज्य काम करने जाते थे तो घर और जमीन पर अवैध कब्जे की चिंता होती थी। कब कहां दूंगा हो जाए, कोई न कह सकता था। बीते साढ़े 4 साल में योगी जी की सरकार स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। मुख्यमंत्री अब माफिया के अवैध निर्माण पर बुलाऊर चलवा रहे हैं। आज यूपी की जनता कह रही है- यूपी + योगी, बहुत

उपयोगी। योगी आदित्यनाथ का एक यूएसपी अपराधियों पर टूट पड़ना, माफियाओं के खिलाफ निर्भक और प्रखर कार्रवाई तथा सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण है। भाजपा हर अवसर पर इसे सामने लाती है और ऐसप्रेसवे के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने इसको जिस तरीके से रखा उसे कुछ लोग अवश्य प्रभावित होंगे। पश्चिम उप्र में भी माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनमें एक विशेष संप्रदाय के वे लोग निशाना बन हैं, जिनके विरोध पूर्व की सरकारें कार्रवाई नहीं कर पाती थीं। इसके साथ मोदीने यह भी कह दिया कि कुछ दल ऐसे हैं जिन्हें देश की विरासत और विकास दोनों से दिक्षित हैं। इन लोगों को बाबा विनाथ का धाम बनने से, राम मंदिर से, गंगा जी की सफाई से दिक्षित है। यही लोग सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों की कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं। इस तरह आध्यात्मिक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के अभृतपूर्व उत्तरान तथा जननामन्त्र से पर इसके असर को ढंग करने की दृष्टि से भी प्रधानमंत्री ने पूरा उपयोग किया। इसमें भाजपा के लिए हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सुरक्षा आदि मुद्दे सब सामने आ गए। पश्चिमी उप्र में यह भावनाएं किंतनी गहरी हैं इसका अंदाजा उन्हें होगा जिन्होंने वहाँ की सामाजिक मनोविज्ञान से वाकिफ होंगे। तो कार्यक्रम अवश्य एक्सप्रेसवे या अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास का हो, भाजपा अपने सारे मुद्दे इसी माध्यम से जनता के सामने रखती है और यह उसको रणनीति है।

## घर में रहते हुए गुजारा भत्ता

## फैसले पर न्यायिक व्यवस्था का इंतजार

अनप भट्टाचार  
अभी तक यही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि अलग-  
रह रही पत्नी या विवाह विच्छेद होने की स्थिति में ऐसे-  
स्त्री और ऐसे दंपति की संतान दंड प्रक्रिया सहिता की-  
धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है। यहीं  
नहीं, संतान की उपेक्षा का शिकार हो रहे माता-पित  
भी इस कानून के तहत भरण-पोषण के हकदार हैं  
लेकिन, क्या पति के साथ एक ही छत के नीचे रहने-  
वाली पत्नी भी धारा 125 के तहत भरण-पोषण भत्ते-  
का दावा कर सकती है? सुनने और पढ़ने में यह थोड़ा-  
अजीब लगे लेकिन यह सवाल इस समय न्यायालय के-  
विचारधीन है।

दिल्ली की एक कुटुम्ब अदालत ने पति के साथ ही उसके-  
घर में रहने वाली पत्नी की याचिका पर उसे गुजारा-  
भत्ता देने का आदेश पति को दिया है। इस आदेश के-  
परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका के समक्ष एक सवाल आया है  
कि क्या पति के साथ ही घर में रहने वाली पत्नी धारा-  
125 के तहत भरण-पोषण भत्ते का दावा कर सकती है। दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 का संबंध पत्नी-  
संतान और माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित है  
इसके अंतर्गत कोई भी स्त्री पति की उपेक्षा या पति से-  
अलग रहने की स्थिति में गुजारा भत्ते की हकदार होती है। यह प्रावधान ऐसे व्यक्ति की संतानों और माता-पिता-  
के मामले में भी लागू होता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त पति की याचिका पर  
अब पत्नी से जवाब मांगा है। पति ने सवाल उठाया है  
कि क्या अपने पति के साथ उसके ही घर में रहने वाली-  
पत्नी धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की हकदार है  
इस मामले में 10 फरवरी को आगे सुनवाई होगी  
लेकिन पिछली तीसरी पर मनवार्ड के दौरान न्यायालय

एक ही घर में उपेक्षित छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिरता  
में पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है।  
सामान्यतया, पति द्वारा पत्नी का परित्याग करने से  
उसके साथ क्रूरता का व्यवहार कर उसे अलग रहने वाले  
लिए मजबूर करने या  
पति द्वारा दूसरी शादी  
कर लेने या पति का  
किसी अन्य महिला के  
साथ रहने, पति के  
किसी सक्रामक रोग  
से ग्रसित होने या पति  
द्वारा धर्घ परिवर्तन कर  
लेने की वजह से पत्नी  
का उससे अलग रहना  
और विवाह विच्छेद  
जैसी परिस्थितियों में  
पत्नी दंड प्रक्रिया  
सहित की धारा 125  
के तहत गान्धा घर्षे के लिए शादीबन्द का दण्डना

करीब तीस हजार रु  
याचिकार्ता पति का दाव  
मिली ग्रेव्युटी की राशि में  
लाख रुपए अपनी पत्नी के

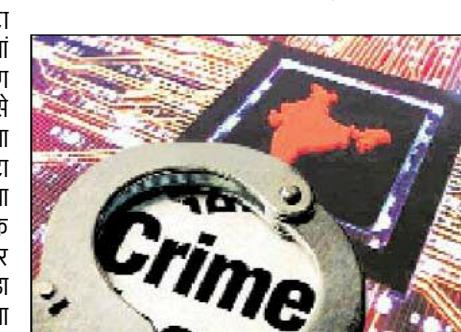
दाखला तास हालार रपैर बतार गुजारा नासा दिला  
अनुरोध किया था।  
चूंकि कुटुम्ब अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की  
125 के तहत गुजारा भरो के लिए मुख्य मामला  
रहने के दौरान पत्नी, अवश्यक संतान, अविवाहित  
और माता या पिता, जैसा प्रकरण हो, अंतरिम गु  
भता देने का आदेश दे सकती है, इसलिए अदाला  
पत्नी को भरण-पोषण के लिए हर महीने दस  
रुपए महीने देने का अंतरिम आदेश दे।

बेहतर प्रशासन

## सटीक डाटा से ही संभव

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दस वर्षों के अंतराल पर 2015–16 में प्रकाशित किया गया था। नतीजा हम पुरानी स्थिति के लिए नियम बनाते हैं, जो वर्तमान के लिए उपयुक्त नहीं।  
वर्तमान में बेदरग दाता

के लिए अच्छे खासे निवेश के साथ स्थानीय कर्मचारी का कौशल विकास भी करना होगा। जमीनी संसदीय शुद्ध डाटा के लिए योजना के साथ तकनीकी का उपयोग



प्रभात सिन्हा  
आजकल देश में डाटा की गुणवत्ता पर बहस जारी है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और ट्रांसपोर्ट एंड रिसर्च विंग के रेकॉर्ड्स में भारी असमानता पाई गई है। यही नहीं कोविड महामारी के डाटा में भी भारी असंगति पाई गई है। हमारे सरकारी विभाग सटीक डाटा सूचना और प्रसार में फिसड़ी साबित हो रहे हैं जिसका नाम हम साप्ताहिक उद्देश्य अधिकारी करता है।

असमर्थ हैं। उदाहरण के तौर पर देश में कोविड के दूसरी लहर की भयावहता को सीमित किया जा सकता था। साथ ही हम अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को व्यवस्थित कर सकते थे। सरकार के पास आतंकवाद के कारण होनेवाली मौतों का भी व्योरा नहीं है, ना ही कोयले वे वर्तमान भंडारण का। बेहतर प्रशासन के लिए शासन वे सभी स्तरों पर सटीक और उत्तम डाटा का सुनन भंडारण और प्रसार अतिआवश्यक हो गया है। दुनिया के सभी विकसित देश डाटा का बेहतर उपयोग साक्षर आधारित नीति निर्धारण के लिए कर रहे हैं। यही नहीं वर्तमान साल 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में भी डाटा की महत्ता को स्वीकार किया गया है। ॥ बस्तर पर विकास की ओर अग्रसर राष्ट्रों को नीति निर्माण के लिए स्फूर्त और प्रभावी तंत्र की आवश्यकता होती है। हमारे देश में नीति निर्माण प्रायः सर्वेक्षण औं परामर्श से होता है लेकिन देश की बड़ी आबादी औं विविधता के कारण डाटा संकलन और नीति निर्माण दोनों बीच बड़ा अंतराल हो जाता है। उदाहरण के लिये, चौथे

आवश्यकता पर बल दिया है। 2001 में डॉ. रंगराजन आयोग की रिपोर्ट में भी जनोपयोगी नीति निर्धारण में डेटा की महत्व को स्वीकार किया गया है। प्रशासन को और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक के योजनाबद्ध और प्रभावी इस्तेमाल की आवश्यकता है। डाटा का संग्रहण और एकत्रीकरण डिजिटल प्रारूप में हो। डाटा का एक केंद्रीय भंडार बने और वहां पर डाटा का भंडारण प्रभावी तरीके से हो, ताकि ग्राम, पंचायत, प्रखंड, जिला इत्यादि का डाटा आवश्यकता अनुसार देखा और उपयोग किया जा सके। नीति आयोग पहले से ही एक नेशनल डाटा एनालिटिक्स पोर्टल पर काम कर रहा, जिसको राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के लिए डाटा का केंद्रीय भंडार बनाने की योजना है। आगे एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस का उपयोग कर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के डाटा का आपस में आदान प्रदान कर एकीकृत भंडारण हो। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित डाटा का सत्यापन कर डाटा की शुद्धता को बढ़ाया जा सकता है। डेटा अभिगम्यता, डाटा गुणवत्ता और डाटा के प्रभावी आदान प्रदान के लिए समरूप और अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल जरूरी है। साथ ही हमें आवश्यक कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर आवश्यक मानव संसाधन को भी तैयार करते रहना होगा। अभी हम डाटा प्रबंधन के शुरू आती चरण में हैं। और बेहतर प्रशासन और नीति निर्धारण के लिए कई आयामों को छूना बाकी है। (लेखक आईटी मामलों के विशेषज्ञ हैं)



# Dheeraj Dhoopar B'day Spl: धीरज धूपर को पहली नजर में हुआ था



# विविध अरोड़ा

## से प्यार, जानें दिलचस्प किसा

धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) को उनके फैंस टीवी शो 'कुंडली भाग्य' से जानते हैं, जिसमें वे करण लूथरा का रोल ले करते हैं। दर्शकों को करण और प्रीता की जोड़ी बेशक बहुत पसंद है, पर धीरज धूपर असल जिंदगी में किसी और के ही दीवाने हैं। वे अपनी पत्नी विन्दी अरोड़ा पर जान छिड़कते हैं। आइए, आज 20 दिसंबर को एकतर के बर्थडे (Happy Birthday Dheeraj Dhoopar) पर उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं।

### टीवी शो के सेट पर मिले थे धीरज और विन्दी

धीरज धूपर का जन्म 20 दिसंबर 1984 को दिल्ली में हुआ था। आज वे अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वे और विन्दी अरोड़ी टीवी जात के जाने-माने एक्टर हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पहली बार टीवी शो 'माता-पिता के चरांगों में स्वर्ग' के शूट पर मिले थे। यह पहली नजर का प्यार था। ज्यादातर लव स्टोरी में जैसा होता है, वैसा ही कुछ इनकी लव स्टोरी में भी हुआ। दोनों के बीच पहली मुलाकात के बाद से ही खूब बातें होने लगीं।

फिर धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उर्ह पता ही नहीं चला। हालांकि, वे शुरू में लोगों की नजरों से अपना प्यार छुपाने में सफल रहे, पर आखिर ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं। लोग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ-साथ उनकी ऑफ स्क्रीन अफेयर को लेकर भी बात करने लगे।

### धीरज ने 6 साल तक विन्दी को किया था डेट

धीरज और विन्दी ने करीब 6 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। फिर कपल ने शादी करने का फैसला किया। तब कपल की शादी में उनके तमाम दोस्त और करीबी शामिल हुए थे। कपल को अक्सर मीडिया के सामने एक-दूसरे की तारीफ करते हुए देखा गया है।

### क्यूट कपल में से एक हैं धीरज और विन्दी

आज उनकी गिनती टीवी इंडस्ट्री के क्यूट कपल में होती है। वे सोशल मीडिया पर खुलकर एक-दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वे अपने फैंस को कपल गोल देते रहते हैं।

**भारती सिंह ने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कहा- बहुत मजा आ रहा है मम्मी बनने में, फैंस ने मांगी Twins की दुआ**



भारती सिंह (Bharti Singh) इन दिनों प्रेनेंट हैं। अपने शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर से सबका मोरोंजन करने वालीं भारती ने अपनी प्रेनेंसी की जानकारी भी सोशल मीडिया पर बड़े ही मजेदार अंदाज में दिया था। अब एक बार फिर भारती ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बेबी बंप फ्लॉन्ट (Bharti Singh Baby Bump) करते नजर आ रही हैं। पिछले दिनों भारती अपने वजन को लेकर चर्चा में थीं। इस फैमस कॉमियन ने पहले से अपना जनन काफी कम कर लिया है। प्रेनेंसी की वजह से भारती इन दिनों भले ही अपने प्रोफेशनल कमिश्नेंट से ब्रेक लिया हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं।

### भारती के मम्मी बनने में आ रहा मजा

भारती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक के बाद एक, अलग-अलग ड्रेस में नजर आ रही हैं। बेहद खूबसूरत हैं। स्टाइल और मेकअप में तेवर हीकर बनाया गया। इस वीडियो को शेयर कर भारती ने कैप्शन में लिखा है- 'मम्मी बनने वाली हूं, बहुत मजा आ रहा है मम्मी बनने में'। भारती का ये वीडियो फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री के सेलेब्स को भी पसंद आ रहा है। सभी भारती को बधाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं।

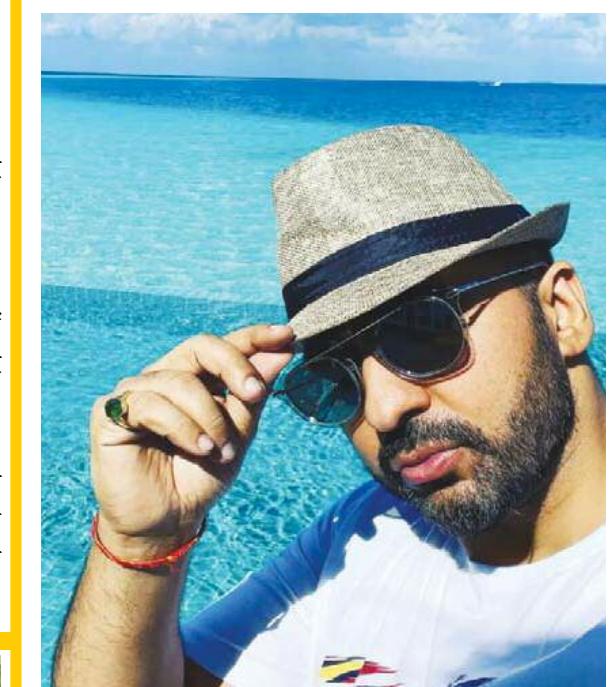
### भारती के फैंस बोले- 'आपके Twins हो जाए'

भारती के इस वीडियो पर एक फैंस ने लिखा '222 मेरी क्यूटी आप सुपर क्यूट मॉम लग रही हैं'। इतना ही नहीं एक ने तो लिखा दिया कि 'बधाई आपके ट्रिवन्स हों मैं चाही हूं कि एक आप जैसी भारती और हर्ष भड़या जैसा हो'।

### भारती की अप्रैल में होगी डिलेवरी

बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया काफी समय से इस वर्क का इतनार कर रहे थे। खबरों की माने तो अप्रैल 2022 में भारती की डिलेवरी होनी है। टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में भारती ने बताया था कि 'शुरुआती दिनों में घबरालों ने गुड न्यूज के बारे में किसी को बताने से मना किया था। इसलिए जब 4 महीने कंपलीट हो गए, तब हमने प्रेनेंसी के बारे में सबको जानकारी दी'।

**राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी केस को लेकर बयां किया दर्द, बोले- आरोप साबित होने से पहले ही दोषी बना दिया**



बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति और बिजेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने पोर्नोग्राफी केस में पहली बार अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने मामले में अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस (Pornography Case) में फंसने के बाद, शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार के लिए पिछले कुछ महीने काफी मुश्किलों भरे रहे। पोर्नोग्राफी मामले में जेल में करीब 2 महीने बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए राज कुंद्रा (Raj Kundra Statement) ने मीडिया से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने और मामले में दखल ना देने की अधीक्षा की है।

### पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा का स्टेटमेंट

राज कुंद्रा ने अपने स्टेटमेंट में कहा- 'बहुत सोच-विचार करने के बाद मुझे लगा कि तमाम गैर-जिम्मेदाराना बयानों और गलत आर्टिकल्स पर मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी समझा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी 'पोर्नोग्राफी' के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं जुड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला कुछ और नहीं बल्कि छुट्टी Hunt है। ये मामला अभी भी विचाराधीन है, इसलिए मैं अभी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन, मैं मुकदमें का साधन करने के लिए तैयार हूं।'

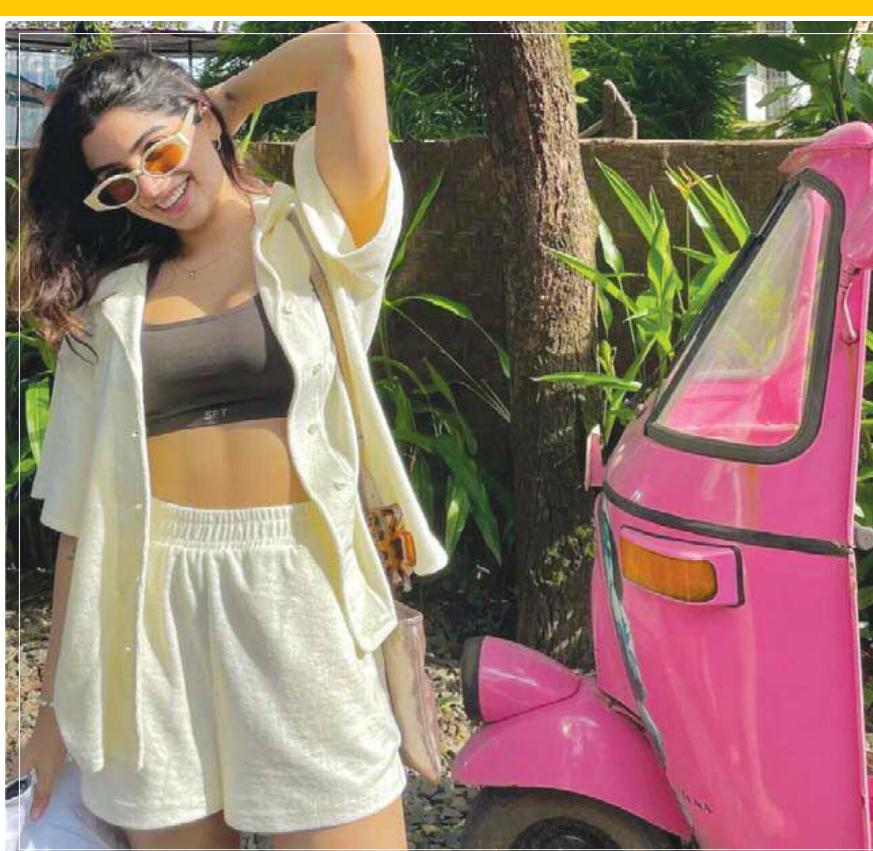
राज कुंद्रा ने अपने बयान में आगे कहा है- 'मुझे भारत की न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जहां सच्चाई की जीत होगी। लेकिन, दुर्भाग्य से मुझ पर लगे आरोप साबित होने से पहले ही मेरे परिवार और मीडिया ने मुझे दोषी समझ लिया और मेरे मानवीय और सांवेदीनिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए दर्द दिया गया।'

**खुशी कपूर**  
ने मिरर सेल्फी शेयर कर दिखाई  
अपने बेडरूम की झलक



खुशी कपूर (Khushi Kapoor) ने अपनी लेटेस्ट फोटो में फैंस को अपने बेडरूम की ज़िल्जाई दिखाई दिया। खुशी ब्राउन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। स्टार किड ने रिव्विवर 19 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर अपनी एक तरीकी शेयर की, जिसमें वे गैरे रंग की बॉडीकॉन ड्रेस में बेडरूम हैं। फोटो में स्टार किड के बेडरूम (Khushi Kapoor Bedroom) की झलक मिल रही है।

खुशी कपूर (Khushi Kapoor) ने अपनी लेटेस्ट फोटो में फैंस को अपने बेडरूम की ज़िल्जाई दिखाई दिया। खुशी ब्राउन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। स्टार किड ने रिव्विवर 19 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर अपनी एक तरीकी शेयर की, जिसमें वे गैरे रंग की बॉडीकॉन ड्रेस में बेडरूम हैं। फोटो में स्टार किड के बेडरूम (Khushi Kapoor Bedroom) की झलक मिल रही है।



मैचिंग साइड टेल भी खुशी की ज़िल्जाई नजर आ रही है। खुशी का विस्तर सफेद बेड शीट से ढका हुआ है। बेड उनकी अलमारी के पास रखा है। चॉकलेट भूरे रंग के लकड़ी के गेट पर नकाशी की गई है। लेकिन, बेड के उलट अलमारी पर डिजाइन बहुत सरल है।

### खुशी का कमरा है बेहद सुंदर

तस्वीर के सबसे आविष्कार में खुशी के शूज कलेक्शन को देखा जा सकता है। उन्होंने अपने शूज के लिए एक पूरी अलमारी बनवाई हुई है, जिसमें सबसे ऊपर हाईल्स रखी दिख रही हैं। बैंक्राउड में खुशी का डॉगी भी नजर आ

रहा है, कमरे में लकड़ी का फर्श है।

मां श्रीदेवी की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती हैं खुशी।

खुशी अपने परिवार, पापा बानी को प्रभाव और बहन जाह्वा की कपूर के साथ मुंबई में रहती हैं। वे हायर स्टडीज के लिए 2019 में अमेरिका चली गई थीं। हालांकि, जब से कोविड-19 महामारी शुरू हुई है, तब से वे ज्यादात समय मुंबई में रहती हैं। बहन जाह्वा और मां श्रीदेवी की तरह, खुशी भी एक एक्ट्रेस बनने की खालिश रहती हैं। ऐसी खबरें हैं कि खुशी जोरा अखर की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेगी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।



## ओमिक्रोन के चलते भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका बायिसंग डे टेस्ट मैच को लेकर आई खबर



एजेंसी, जोहानिसबर्ग। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से खेला जाएगा, जो कि बायिसंग डे टेस्ट मैच है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेन्ट्रलिंग में शुरू होने वाला पहला टेस्ट दर्शकों के बिना खेला जाएगा, क्योंकि मेजबान देश का क्रिकेट बोर्ड नए कोविड - 19 वैरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए टिकट नहीं बेच रहा है। केवल कुछ ही लोग मैच को लाइव देख पाएंगे। हालांकि, सरकार द्वारा लागू वर्तमान कारोना प्रोटोकॉल के तहत

दो हजार प्रशंसकों के लिए अनुमति है, लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका यानी सीएसए इस समय किसी भी प्रकार का खेतरा मोल लेने की स्थिति में नहीं है।

यही कारण है कि कम से कम फिलहाल के लिए पहला टेस्ट बंद दरवाजों के पाठे आयोजित होगा। हालांकि, आयोजक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या अगले सप्ताह कोविड - 19 के संबंध में सरकारी नियमों में कोई बदलाव होता है या नहीं। बांडर्स में तीन जनवरी से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट के लिए फिलहाल कोई टिकट नहीं बिक रहा है। स्टेंडिंगमें आधारिक अंगठी को लाइव देख पाएंगे।